

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2023

(2) "स्थल चयन समिति" द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने एवं अतिक्रमण से मुक्त होने आदि का संज्ञान लेने के साथ-साथ सिविल/वन भूमि हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि अर्जन, यथालागू सम्बन्धी प्रक्रिया योजना का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व सम्पन्न कर लिए जाने की स्थिति/संभावना का भी आंकलन किया जायेगा।

(3) किसी विभाग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर "स्थल चयन समिति" एक सप्ताह के भीतर स्थल चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेगी।

(4) परियोजना की प्रकृति के अनुसार भूमि/स्थान की उपयुक्तता के आधार पर समिति उक्त बिन्दु 3(1) एवं 3(2) के आलोक में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सिविल भूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, किन्तु सिविल भूमि उपलब्ध न होने अथवा उक्त मानकों की दृष्टि में उपयुक्त न पाये जाने की दशा में उक्त मानकों की दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त वन भूमि के हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में भी स्थल चयन कर अपनी संस्तुति देगी।

(5) प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ स्थल चयन समिति की आख्या संलग्न की जानी आवश्यक होगी जिसमें उपयुक्तता के कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में स्थल चयन समिति वरीयता के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के स्थलों का चयन कर उसके कारणों सहित अपना मंतव्य देगी।

(7) परियोजना की डी.पी.आर. का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षण तभी किया जायेगा जबकि उसमें स्थल चयन समिति की रिपोर्ट संलग्न हो। साथ ही, परियोजना की स्वीकृति के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी/वित्त विभाग द्वारा यह भी देखा जायेगा कि परियोजना के सन्दर्भ में स्थल चयन की कार्यवाही शासनादेश के अनुसार की गयी है।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ऐतद्विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 90214/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 तथा शासकीय परियोजनाओं के निमित्त निःशुल्क भूमि की अनिवार्यता विषयक राजकीय विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत अन्य शासनादेश, यदि कोई हों, अवक्रमित समझे जायेंगे।

5. कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Signed by Sukhbir Singh

Sandhu

Date: 09-06-2023 15:01:39

(डॉ. सुखबीर सिंह सन्धु)

मुख्य सचिव

संख्या : 128475 / XXVIII(1) / 2022 एवं तदुद्दिनांकित । 12/06/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)

सचिव